

अनुदान संख्या 71 - योजना मंत्रालय
GRANT No. 71-MINISTRY OF PLANNING

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	121,82,00	78,53,05	-43,28,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			40,56,25
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	7,50,00	3,36,70	-4,13,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,50,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	4602.00	4549.75	4264.20
पु.	R.	-52.25		
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities			
मू.	O.	300.00	28.00	16.86
पु.	R.	-272.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services			
मू.	O.	6680.00	2911.00	2935.01
पु.	R.	-3769.00		
(I) मुख्य शीर्ष "3451" - "योजना आयोग/योजना बोर्ड" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-		(I) Under Major Head "3451" - "Planning Commission/Planning Board" - savings occurred under the following heads:-		
(का) "कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण" - 194.72 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एम्पोरियमों को दिए गए कार्य को पूरा न किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मुख्य निर्माण कार्यों का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।		(A) "Modernisation of Office Systems" - saving of Rs.194.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to non-completion of work awarded to Emporiums and non-execution of major works through Central Public Works Department.		
(खा) "प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद" - 117.59 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, घरेलू एवं विदेश यात्राओं पर कम व्यय होने और बैठकों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का कम आयोजन किए जाने के कारण हुई।		(B) "Economic Advisory Council to the Prime Minister" - saving of Rs.117.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less expenditure on domestic and foreign tours and holding of less meetings/seminars/conferences.		
(II) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - प्राकृतिक विपत्ति प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम" के अंतर्गत 283.14 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रभावी अध्ययन से संबंधित प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।		(II) Under Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters, Contingency Plans in Disaster Prone Areas - Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.283.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for Impact Studies from Tsunami affected States/Union Territories.		
(III) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-		(III) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-		
(का) "सरकार को जनशक्ति अनुसंधान सेवाएं आदि" - 193.00 लाख रु. की बचत (680.00 लाख रु. के स्वीकृत		(A) "Manpower Research Services to Government etc." - saving of Rs.193.00 lakhs		

प्रावधान की तुलना में) अध्ययन से संबंधित पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “राज्य मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता” - 737.00 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और राज्यों एवं राष्ट्रीय संसाधन संस्थानों द्वारा कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(गा) “योजना के 50वें वर्ष की शुरुआत” - 272.65 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन से संबंधित कम प्रस्तावों के प्राप्त होने, रिपोर्टों के मुद्रण से संबंधित दावों के प्राप्त न होने और विवेकाधीन अनुदानों/पुरस्कारों पर कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(घा) “सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढीकरण” - 2540.80 लाख रु. की बचत (2600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(against the sanctioned provision of Rs.680.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient study proposals.

(B) “Assistance from UNDP for Preparation of State Human Development Reports” - saving of Rs.737.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to non-finalisation of some projects and less expenditure by States and National Resource Institutions.

(C) “50th Year Initiative for Planning” - saving of Rs.272.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to receipt of less study proposals, non-receipt of claims relating to printing of reports and less payment on discretionary grants/awards.

(D) “Strengthening Evaluation Capacity in Government” - saving of Rs.2540.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2600.00 lakhs) was due to non-implementation of various evaluation studies.

2. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष “5475” अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Head Major Head “5475” Capital Outlay on Other General Economic Services
मू.	O. 750.00
पु.	R. -350.00

(I) “अन्य व्यय - कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण” के अंतर्गत 413.30 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम्प्यूटरों, साफ्टवेयर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों से संबंधित विभिन्न क्रयों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under “Other Expenditure – Modernisation of Office Systems” – saving of Rs.413.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to non-finalisation of various purchases relating to computers, software and other Information Technology equipments.